# इकाई 20 बेरोज़गारी

**इकाई की रूपरेखा**


20.0 उद्देश्य
20.1 प्रस्तावना
20.2 बेरोज़गारी का अर्थ
20.3 भारत में बेरोज़गारी का स्वरूप
  20.3.1 ग्रामीण बेरोज़गारी
  20.3.2 शहरी बेरोज़गारी
20.4 बेरोज़गारी के कारण
  20.4.1 धीमी संवृद्धि प्रक्रिया
  20.4.2 श्रमशक्ति में वृद्धि
  20.4.3 अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी
  20.4.4 अनुपयुक्त शिक्षा पद्धति
20.5 बेरोज़गारी की माप
  20.5.1 सामान्य स्थिति बेरोज़गारी
  20.5.2 चालू साप्ताहिक स्थिति
  20.5.3 चालू दैनिक स्थिति
  20.5.4 बेरोज़गारी की समस्या का आकार
  20.5.5 शिक्षा और बेरोज़गारी
  20.5.6 महिलाओं में बेरोज़गारी का आर्थिक आपात
  20.5.7 बेरोजगारी का क्षेत्रीय आयाम–नवीं पंचवर्षीय योजना
20.6 बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए सरकारी नीति
  20.6.1 नवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व रोजगार नीति
  20.6.2 नवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार परिदृश्य
20.7 रोज़गार कार्यक्रमों का विवरण
  20.7.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम
  20.7.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
  20.7.3 भूमिहीन ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम
  20.7.4 जवाहर रोज़गार योजना
  20.7.5 स्वरोज़गार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण
20.8 सारांश
20.9 शब्दावली
20.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें
20.11 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत


## 20.0 उद्देश्य

यह इकाई भारत में बेरोज़गारी की समस्या तथा इस संबंध में अपनाई गई नीति की चर्चा करती है। इसको पढ़ने के बाद आप बता पाएँगे :

- बेरोज़गारी का अर्थ;
- भारत में पाई जाने वाली बेरोज़गारी के प्रकार;
- भारत में बेरोज़गारी की माप;
- बेरोज़गारी के कारण;

- बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए सरकारी नीति; तथा
- विभिन्न बेरोज़गारी उन्मूलन कार्यक्रम।

## 20.1 प्रस्तावना

रोज़गार अवसरों में वृद्धि भारत में अर्थनैतिक विकास का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। हालाँकि पिछले वर्षों में रोज़गार अवसरों में भारी वृद्धि हुई है लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण, बेरोज़गारी में लगातार वृद्धि हुई। सभी बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोज़गारी एक साधारण बात है चाहे उनके विकास का स्तर कैसा भी हो। लेकिन एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में भारी गरीबी के कारण, बेरोज़गारी दुःखदाई तो है ही, साथ ही साथ यह संसाधनों की बरबादी की ओर भी इंगित करती है, जिनको देश के विकास के लिए प्रयोग किया जा सकता था। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बेरोज़गारी उन्मूलन एक मूल उद्देश्य है।

## 20.2 बेरोज़गारी का अर्थ

साधारण शब्दों में, एक व्यक्ति जो किसी उत्पादक गतिविधि में लाभकारी कार्य कर रहा हो उसे बेरोज़गार कहेंगे। बेरोज़गारी में अंतर करने की कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। साधारणतया किसी अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी 15-59 वर्ष के आयु वर्ग तक सीमित होती है। यानि बच्चे और बुजुर्गों को हम बेरोज़गारी की परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं करते। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सभी लोग (पुरुष, महिलाएँ और बच्चे) जो काम करते हैं तथा जो काम नहीं करते लेकिन काम की तलाश में हैं, उन सभी को बेरोज़गार मानना चाहिए। अर्थव्यवस्था में एक ऐसा वर्ग होता है जो किसी लाभकारी रोज़गार में इच्छुक नहीं होता। ऐसे लोग भी होंगे जो प्रचलित मजदूरी दर से अधिक मिलने पर काम के लिए इच्छुक होंगे। उपरोक्त दो प्रकार की श्रेणियों में आने वाले लोगों को ऐच्छिक रूप से बेरोज़गार कहेंगे।

अनैच्छिक बेरोज़गारी वह स्थिति है जब लोग चल रही मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं होते।

अर्थशास्त्र में हम अनैच्छिक बेरोज़गारी को ही बेरोज़गारी मानते हैं, ऐच्छिक बेरोज़गारी को नहीं।

अल्पविकसित देशों में बेरोज़गारी की स्थिति, विकसित देशों में बेरोज़गारी से भिन्न होती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोज़गारी अथवा घर्षणात्मक बेरोज़गारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोज़गारी प्रभावपूर्ण माँग में कमी के कारण तथा घर्षणात्मक बेरोज़गारी तकनीक में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है।

दूसरी ओर अल्पविकसित देशों में बेरोज़गारी संरचनात्मक प्रकार की होती है। अल्पविकसित देशों में कृषि के पिछड़ेपन, अल्पविकसित उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र के लघु आकार के कारण श्रम की माँग कम होती है। हालाँकि अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी अनैच्छिक बेरोज़गारी की श्रेणी में मानी जाएगी लेकिन यह विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी से भिन्न है।

**बोध प्रश्न 1**

1) ऐच्छिक बेरोज़गारी से आपका क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अनैच्छिक बेरोज़गारी से आपका क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी, विकसित देशों में पाई जानी वाली बेराजगारी से किस प्रकार से भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.3 भारत में बेरोज़गारी का स्वरूप

भारत में पाई जाने वाली बेरोज़गारी विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी से भिन्न है। भारत एक अल्पविकसित परंतु विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ यह बताना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में पाई जाने वाली बेरोज़गारी प्रभावपूर्ण माँग (effective demand) की कमी के कारण नहीं बल्कि पूँजीगत वस्तुओं और उसके पूरक संसाधानों की कमी के कारण होती है। भारत में कई प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है। साधारण तौर पर इसके दो प्रकार हैं– ग्रामीण बेरोज़गारी तथा शहरी बेरोज़गारी।

### 20.3.1 ग्रामीण बेरोज़गारी

भारत में पाई जाने वाली बेरोज़गारी का एक प्रमुख हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रामीण बेरोज़गारी के प्रमुख आयाम हैं– मौसमी तथा चिरकालिक प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ग्रामीण भारत में कृषि एक प्रमुख रोज़गार है। कृषि एक मौसमी रोज़गार है। इसलिए अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या वैकल्पिक रोज़गार के न होने के कारण, बेरोज़गार रहती है। अनुमान है कि कृषि में लगी जनसंख्या का एक बड़ा भाग वर्ष में 5–7 माह तक बेकार रहता है।

ग्रामीण क्षेत्र का दूसरा आयाम चिरकालिक प्रच्छन्न बेरोज़गार का है। 1991 की जनगणना के अनुसार दो तिहाई जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा सहायक गतिविधियों) में लगी है। कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या निर्बाध रूप से लगातार बढ़ रही है। जबकि 1951 में

केवल 10 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे, 1991 में यह संख्या बढ़कर 23.73 करोड़ हो चुकी थी। कृषि भूमि में पर्याप्त वृद्धि के बिना, इस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि में भीड़-भाड़ का कारण बनता है। यह एक ऐसी स्थिति है कि यदि अतिरिक्त श्रम को कृषि से हटा भी ली जाए, तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। (शर्त यह है कि बड़ी हुई श्रमशक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करें) इस प्रकार की स्थिति को प्रच्छन्न बेरोज़गारी (disguised unemployment) कहते हैं। नर्कसे (Nurkse) के शब्दों में अतिरिक्त श्रमशक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इस प्रकार की बेरोज़गारी की प्रमुख समस्या यह है कि इस प्रकार की बेरोज़गारी में हालाँकि सभी रोज़गार युक्त तो प्रतीत होते हैं लेकिन सभी को पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होता। प्रच्छन्न बेरोज़गारी की अवधारणा को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। माना कि 10 लोग खेत में काम कर रहे हैं, जबकि उनके लिए पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं हैं। यह काम खेत में कार्यरत सभी लोगों में विभाजित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोगों को खेत में से निकाल लिया जाए, और खेत में बचे बाकी लोग उस कार्य को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार करें ताकि उत्पादन न घटे, तो अतिरिक्त श्रम जो कि खेत से निकाला जाता है, वह प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाएगी।

शिक्षित बेरोज़गारी ग्रामीण बेरोज़गारी का एक उभरता हुआ आयाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के साथ, कृषि क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग उभरा है जो शिक्षित है। इनमें से कुछ लोग तो अत्यंत ऊँचे दर्जे की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। साधारण कृषि कार्यों में वे अपने आपको उपयुक्त नहीं पाते। परंपरागत ग्रामीण प्रौद्योगिकी और उनकी शिक्षा एवं प्रतिभा के बीच सामंजस्य नहीं होता। शहरी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोग बेरोज़गार रहते हैं। ग्रामीण बेरोज़गारी की अवधारणा को समझना ग्रामीण निर्धनता को समझने के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन वास्तव में बेरोज़गार या अल्प-रोज़गार से लगे होते हैं। वे आमतौर पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर तथा सीमांत किसान होते हैं। इसलिए, ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए बेरोज़गारी को दूर करना आवश्यक है।

### 20.3.2 शहरी बेरोज़गारी

जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोज़गारी प्रमुख रूप से प्रच्छन्न बेरोज़गारी है, शहरी क्षेत्र में बेरोज़गारी खुली बेरोज़गारी होती है। शहरी बेरोज़गारी, भारी सामाजिक तनाव का कारण बनता है।

पहली प्रकार की शहरी बेरोज़गारी अशिक्षित औद्योगिक श्रमिकों के रूप में है। इस बेरोज़गारी को 'ब्लू कॅलार' (blue collar) बेरोज़गार के नाम से भी जाना जाता है। हालाँकि औद्योगिक क्षेत्र में भारी विकास हुआ है, औद्योगिक बेरोज़गारी में भी साथ ही साथ भारी वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हैं :

- देश में आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से जनसंख्या का स्थानांतरण जिसके कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि से अधिक तेजी से हुई है। इसके अतिरिक्त कम काम वाले मौसम में ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिक शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का जमाव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का पतन।

दूसरी प्रकार की शहरी बेरोज़गारी 'शिक्षित मध्यम वर्गीय बेरोज़गारी' है। ऐसे बेरोज़गारों को 'व्हाइट कॅलार' बेरोज़गार कहते हैं। शिक्षित बेरोज़गारी के कई कारण है। पहला, शिक्षित

जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा सुविधाओं में भारी विस्तार लेकिन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ उस दर से नहीं बढ़ीं। दूसरा, आर्थिक समृद्धि की दर काफी धीमी रही, जिसके कारण रोज़गार के अवसरों में वृद्धि कम हुई। रोज़गार के अवसर सभी प्रकार के शिक्षित लोगों के लिए कम बढ़े, चाहे वे इंजीनियर हों, तकनीक कार्मिक हों अथवा कला एवं वाणिज्य स्नातक या स्नातकोत्तर। 1951 में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या मात्र 2.44 लाख थी, जो 1980 में बढ़कर 34.72 लाख हो गई। 1985 में यह संख्या 47 लाख थी और 1992 तक यह बढ़कर 68 लाख हो चुकी थी। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अनुसार 1983 और 1993 के बीच, शिक्षित बेरोज़गारों मे सैकेण्डरी या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त बेरोज़गारों की संख्या 47 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई। साक्षरों में बढ़ती बेरोज़गारी हमें यह ध्यान दिलाती है कि किस प्रकार से शिक्षा में लगे संसाधनों का भरपूर लाभ देश के लिए नहीं हो पाता। इस प्रवृत्ति से यह भी इंगित होता है कि उपलब्ध रोज़गार के अवसरों और रोज़गार की आवश्यकता के बीच सामंजस्य नहीं है। बेरोज़गारों में साक्षरों की बढ़ती संख्या और उनमें से भी अधिक पढ़े लिखे लोगों की संख्या इंगित करती है कि हमें कम उत्पादकता वाले शारीरिक रोज़गार की अपेक्षा कुशल रोज़गार के अवसरों की अधिक आवश्यकता है।

बेरोज़गारी की एक अन्य उभरती प्रवृत्ति उन लोगों की है जो अध्ययन के दौरान पार्ट टाइम काम की तलाश में रहते हैं। इस प्रकार के लोग यदि अपनी संतुष्टि के अनुसार रोज़गार पाने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें बेरोज़गार कहना गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और अपनी क्षमताओं और योग्यता के अनुसार रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते।

**बोध प्रश्न 2**

1) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-सी दो प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में प्रच्छन्न बेरोज़गारी की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत के शहरी क्षेत्रों में कौन-से प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.4 बेरोज़गारी के कारण

पिछले भाग में हमने भारत में बेरोज़गारी की प्रवृत्तियों तथा संरचना के बारे में पढ़ा और इस समस्या की गंभीरता के बारे में जाना। आइए अब हम बेरोज़गारी के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करें।

i) संवृद्धि की धीमी प्रक्रिया।

ii) श्रमशक्ति में वृद्धि।

iii) अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी

iv) अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली तथा मानव शक्ति आयोजन की कमी।

### 20.4.1 संवृद्धि की धीमी प्रक्रिया

इस बात में कोई संदेह नहीं कि विकसित तथा अल्पविकसित दोनों प्रकार के देशों में बेरोज़गारी पाई जाती है। विकसित देशों में आय के ऊँचे स्तर के बावजूद, वहाँ भी बेरोज़गारी विद्यमान रहती है। लेकिन अल्पविकसित देशों में बेरोज़गारी विकास के निम्न स्तर तथा धीमी संवृद्धि प्रक्रिया के कारण होती है।

यह अपेक्षित ही है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था संवृद्धि पथ पर अग्रसर होती है, उत्पादन बढ़ता है और साथ ही रोज़गार भी। हम पाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्पादन में संवृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। लेकिन संवृद्धि दर अपेक्षित दर से कम रही है जिसके फलस्वरूप रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल आर्थिक संवृद्धि बेरोज़गारी समस्या का समाधान नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने रोज़गार तथा आर्थिक संवृद्धि के प्रारंभिक काल में परस्पर द्वंद्व की ओर इंगित किया है। भारत में भी यह द्वंद्व काफी स्पष्ट है। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना तक इस द्वंद्व को मान्यता नहीं दी गई। जिसके फलस्वरूप आर्थिक संवृद्धि के कारण रोज़गार के स्थूल अवसर तो बढ़े लेकिन बेरोज़गारी की समस्या के समाधान में वे काफी नहीं थे।

### 20.4.2 श्रम शक्ति में वृद्धि

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पिछले पचास वर्षों में श्रमशक्ति में भारी वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मृत्युदर में तेजी से कमी हुई है, जबकि जन्मदर में उतनी तेजी से कमी नहीं हुई। इस कारण से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इस प्रकार से श्रमशक्ति में तेजी से वृद्धि स्वाभाविक है।

शहरीकरण और रोज़गार के प्रति बदले दृष्टिकोण के कारण भी श्रमशक्ति में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के कारण उनके रोज़गार के प्रति दृष्टिकोण में काफी अंतर आया है। वे पुरुषों के साथ रोज़गार के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्र में अधिक विद्यमान है।

श्रमपूर्ति में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है : (i) तेजी से बढ़ती जनसंख्या, (ii) महिलाओं में रोज़गार के प्रति बदले दृष्टिकोण, तथा (iii) संवृद्धि प्रक्रिया के अतिरिक्त रोज़गार सृजन में असमर्थता। इन सब कारणों ने बेरोज़गारी की समस्या को कई गुणा बढ़ा दिया है।

### 20.4.3 अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी

हम समझते हैं कि भारत में श्रम की प्रचूरता है जबकि पूँजी की कमी है। इसलिए बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें एक निश्चित उत्पादन के लिए पूँजी का कम तथा श्रम का अधिक उपयोग हो। वास्तव में हम श्रम का कम और पूँजी का अधिक उपयोग करते हैं। यह बात केवल उद्योगों में ही नहीं बल्कि कृषि में भी लागू होती है।

प्रौद्योगिकी का चयन करते हुए, साधारणतः पश्चिमी मॉडल की नकल करते हैं। हम जानते हैं कि पश्चिम में श्रम की कमी है जबकि पूँजी की प्रचूरता है। इसलिए उनके लिए उचित प्रौद्योगिकी वही है जो पूँजी प्रधान हो। लेकिन भारत में हम अधिक जटिल पूँजी प्रधान प्रौद्योगिकी के प्रयोग को उचित नहीं ठहरा सकते हैं जो श्रम को प्रतिस्थापित करे। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेरोज़गारी में भारी वृद्धि हुई है।

ऐसे में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पूँजी की भारी कमी और श्रम की प्रचूरता के बावजूद भारत में पूँजी प्रधान तकनीकों का उपयोग क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि पूँजी और श्रम के प्रतिफल बाजार में निर्धारित नहीं होते। एक ओर जहाँ श्रम को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाती है दूसरी ओर ब्याज दर को जानबूझ कर नीचा रखा जाता है। इस कारण से लोग पूँजी प्रधान तकनीक को उपयोग करने की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह आर्थिक रूप से अधिक लाभदाई होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसी स्थिति में पूँजी प्रधान तकनीक का उपयोग पूँजीपति के लिए तो लाभदायक हो सकता है लेकिन यह समाज के लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि इससे बेरोज़गारी बढ़ती है।

### 20.4.4 अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली

हमने अपने औपनिवेशिक शासकों से अपनी शिक्षा प्रणाली विरासत में पाई है। मैकॉले (Macaulay) ने औपनिवेशिक काल में शिक्षा प्रणाली की रचना करते हुए ब्रिटिश हितों का ध्यान रखा। मैकॉले ने ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जो ब्रिटिश सरकार के लिए निम्न श्रेणी के अफसर तथा क्लर्क बना सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कला तथा वाणिज्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थाओं का विस्तार हुआ। तकनीकी, इंजीनियरिंग तथा चिकित्साशास्त्र की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थानों का बहुत कम विस्तार हुआ। इस कारण से शिक्षित पुरुष और महिलाओं की बेरोज़गारी में भारी वृद्धि हुई, जबकि तकनीकी तथा विशेषज्ञ कर्मियों की कमी बनी रही। इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को एक उपयुक्त शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने की आवश्यकता है जो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधनों का विकास कर सके।

दूसरी ओर हमारे यहाँ श्रमशक्ति आयोजन (man pawer planning) का नितांत अभाव है। किसी भी अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास में मानव संसाधनों की एक प्रमुख भूमिका होती है। विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त योग्यताओं को उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालीन आयोजन की आवश्यकता होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि उच्च शिक्षा,

तकनीकी शिक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन वे विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त मानव संसाधन हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में मानव संसाधनों की कमी है। हम पाते हैं कि स्नातक, स्नातकोत्तर तथा कला विषयों पर शोधकर्ताओं के बीच भी बेरोज़गारी विद्यमान है जबकि चिकित्सकों, इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों की कमी बरकरार है।

**बोध प्रश्न 3**

1) आपकी राय में भारत में बेरोज़गारी के प्रमुख कारण कौन से हैं? विस्तार से बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.5 बेरोज़गारी का मापन

प्रचलित एवं परंपरागत अवधारणा के अनुसार बेरोज़गारी से अभिप्राय है बेकारी। यानि वह समय जिसमें लोग काम करने के इच्छुक है और काम के लिए उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसमें प्रच्छन्न बेरोज़गारी अथवा अल्प रोज़गार सम्मिलित नहीं माना जाता। यानि काम की वह स्थिति जिसमें अत्यंत निम्न उत्पादकता तथा आय होती है। भारत में बेरोज़गारी की समस्या परंपरागत रूप से मापी जाने वाली बेरोज़गारी से कहीं अधिक व्यापक है। कम आय वाले लोग बेरोज़गार नहीं रह सकते, इसलिए किसी भी उपलब्ध कार्य को करने लगते हैं चाहे उससे उन्हें कम आय प्राप्त हो। इस प्रकार परंपरागत तरीके से मापने पर बेरोज़गारी की दर कम आना स्वाभाविक है। हम यह भी जानते हैं कि श्रमिकों की संख्या की दृष्टि से ये प्रमुख क्षेत्र है। इसलिए बेरोज़गारी की समस्या के मापन तथा विश्लेषण के लिए बेरोज़गारी की परंपरागत अवधारणा पूर्ण नहीं है। इस तथ्य को समझते हुए राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण (National Sample Survey) तीन अवधारणाओं के आधार पर बेरोज़गारी की दर प्रस्तुत करता है। बेरोज़गारी की ये तीन अवधारणाएँ इस प्रकार से हैं।

1) सामान्य स्थिति (usual status) बेरोज़गारी
2) चालू साप्ताहिक स्थिति (current weekly status) बेरोज़गारी
3) चालू दैनिक स्थिति (current daily status) बेरोज़गारी

### 20.5.1 सामान्य स्थिति बेरोज़गारी

एक व्यक्ति सामान्य आधार पर बेरोज़गार माना जाएगा जब वह लंबे समय से कार्यरत न हो लेकिन काम की इच्छा रखता है या काम के लिए उपलब्ध है। संदर्भ वर्ष (reference year) में सामान्य स्थिति बेरोज़गारी दर चिरकालिक बेरोज़गारी की माप समझी जाएगी। यह माप चिरकालिक अथवा एक लम्बे समय तक बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या प्रदान करती है। यह बेरोज़गारी की संकीर्णतम अवधारणा है क्योंकि यह बेरोज़गारी का न्यूनतम अनुमान देती है। क्योंकि भारत जैसे गरीब देश में बहुत कम लोग लम्बे समय तक बेरोज़गार रह सकते हैं और इसलिए वे कम अवधि के लिए भी काम ले लेते हैं।

### 20.5.2 चालू साप्ताहिक बेरोज़गारी

इस माप में संदर्भ काल एक सप्ताह होता है। एक व्यक्ति चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी के संदर्भ में बेरोज़गार माना जाएगा जब उस संदर्भ सप्ताह में उसे एक घंटे के लिए भी काम न मिला हो। चालू साप्ताहिक स्थिति भी चिरकालिक बेरोज़गारी का माप है लेकिन इसमें संदर्भ काल केवल एक सप्ताह रह जाता है। यह बेरोज़गारी की एक संकीर्ण अवधारणा है लेकिन यह सामान्य स्थिति बेरोज़गारी से अधिक व्यापक है। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यक्ति रोज़गार युक्त माना जाएगा, चाहे वह उस सप्ताह के आखिरी दिन मात्र एक घंटे के लिए ही रोज़गार-युक्त रहा हो। ध्यान देने योग्य है कि यह अवधारणा बेरोज़गार व्यक्तियं की संख्या प्रदान नहीं करती। वह व्यक्ति सप्ताह (Person Week) के रूप में अप्रयुक्त समय का अनुमान प्रस्तुत करता है।

### 20.5.3 चालू दैनिक बेरोज़गारी

चालू दैनिक बेरोज़गारी की अवधारणा बेरोज़गारी के कुल व्यक्ति दिवस (man days) के रूप में दी जाती है। इस अवधारणा के अनुसार बेरोज़गारी का यह माप, श्रमशक्ति में एक संदर्भ सप्ताह में सभी बेरोज़गार लोगों के बेरोज़गारी दिवसों का मापन होता है। चूँकि बेरोज़गारी का यह माप चिरकालिक बेरोज़गारी के साथ साप्ताहिक आधार पर अल्प रोज़गार के माप उपलब्ध करता है, इसलिए यह बेरोज़गारी की सर्वाधिक व्यापक माप है। पुनः यह ध्यान में रखना होगा कि यह बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित नहीं करता। यह व्यक्ति दिवसों के रूप में अप्रयुक्त समय का माप है।

### 20.5.4 बेरोज़गारी की समस्या का आकार

पिछले भागों में हमने बेरोज़गारी की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा की। आइए हम अब समस्या के आकार एवं अन्य आयामों के बारे में चर्चा करें।

**तालिका 20.1**

**जनसंख्या, श्रम शक्ति तथा रोज़गार**

(10 लाख)

| | 1978[a] | 1983[b] | 1994[a] | 1997[c] | 2002[c] | 2007 [c] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | 637.6 | 725.80 (2.92) | 893.67 (2.00) | 649.89 (1.89) | 1027.61 (1.59) | 1107.51[c] (1.51) |
| श्रमशक्ति | 262.57 | 289.08 (2.16) | 367.39 (2.31) | 397.22 (2.43) | 450.23 (2.54) | 509.35 (2.50) |
| रोज़गार | 255.46 | 283.22 (2.32) | 259.98 (2.31) | 389.72 (2.47) | 443.60 (2.62) | 509.35[d] (2.80) |
| बेरोज़गार | 7.11 | 5.86 | 7.41 | 7.5 | 6.63 | नगण्य[1] |

**नोट** :

1) श्रमशक्ति एवं रोज़गार पर अनुमान सामान्य स्थिति अवधारणा पर आधारित हैं और 1: वर्ष तथा अधिक के आयु वर्ग के लिए हैं।

2) कोष्ठक में दिए आँकड़े पूर्व काल के चक्रवृद्धि वृद्धि-दर के हैं–

a) पहली जनवरी को

b) 1 जुलाई को

c) 1 अप्रैल को

d) पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने हेतु

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना अयोग, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि सामान्य बेरोज़गारी के आधार पर बेरोज़गारों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है जबकि रोज़गार की वृद्धि दर में 1994 के पूर्व के दशक में कोई सुधार नहीं हुआ है। नवीं पंचवर्षीय योजना में रोज़गार सृजन की वृद्धि की अपेक्षित दर को 2.62% प्रतिवर्ष निर्धारित किया और बेरोजगारों की संख्या को 1997 में 75 लाख से घटाकर 2002 तक 66.2 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 2007 तक बेरोज़गारी को नगण्य (न के बराबर) करने का लक्ष्य रखा गया।

चालू साप्ताहिक अवधारणा के अनुसार, बेरोज़गार लोगों का अनुपात 1983 में 20 प्रति हजार से घटकर 1993-94 में 14 प्रति हजार रह गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले दशक में बेरोज़गारी का आपात कम हुआ है, खास तौर पर हाल ही के वर्षों में बेरोज़गारी में उल्लेखनीय कमी हुई है। साप्ताहिक अवधारणा के आधार पर 1993-94 में 8.6 प्रतिशत लोग बेरोज़गार थे जबकि 1983 में 15.6 प्रतिशत तथा 1987-88 में 14.6 प्रतिशत लोग बेरोज़गार थे।

**तालिका 20.2**

**चालू साप्ताहिक अवधारणा के आधार पर सामान्यतः रोज़गार युक्त व्यक्तियों का विवरण।**

**संपूर्ण भारत (व्यक्ति)**

| चालू साप्ताहिक अवधारणा के आधार पर गतिविधि | सामान्यतः रोजगार युक्त (प्रति हजार) | | |
|---|---|---|---|
| | **1993-94** | **1987-88** | **1983** |
| 1) रोज़गार युक्त | 914 | 854 | 844 |
| 2) कार्य से बाहर, क्योंकि | 86 | 146 | 156 |
| a) बेरोज़गार | 14 | 17 | 22 |
| b) श्रमशक्ति से बाहर | 72 | 128 | 133 |
| 3) सभी सामान्यतः रोज़गार युक्त (1+2) | 1000 | 1000 | 1000 |

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

तालिका 20.3 में श्रमशक्ति में बेरोज़गारी तथा अल्परोज़गार के आपात को सम्मिलित रूप में बताया गया है। इस तालिका से हमें पता चलता है कि 1993-94 में खुली बेरोज़गारी कुल श्रमशक्ति का मात्र 2 प्रतिशत ही था, जबकि बेरोज़गारी तथा अल्परोज़गार का कुल आपात 10.45 प्रतिशत था।

तालिका 20.3

**बेरोज़गारी तथा अल्प रोज़गार का संयुक्त आपात**

| अवधारणा | श्रम शक्ति का अनुपात | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1. श्रमशक्ति | 100.00 | सामान्य स्थिति आधार पर कार्यरत अथवा काम के इच्छुक |
| 2. रोज़गार युक्त | 89.55 | सामान्य स्थिति रोज़गार युक्त श्रम शक्ति, साप्ताहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत |
| 3. बेरोज़गार | 2.02 | सामान्य स्थिति आधार पर खुली बेरोज़गारी का आपात |
| 4. अल्प रोज़गार युक्त | 8.43 | अपने साप्ताहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत सामान्य स्थिति रोज़गार युक्त |
| 5. बेरोज़गार तथा अल्परोज़गार युक्त (3+4) | 10.45 | सामान्य स्थिति के आधार पर खुली बेरोज़गारी तथा सामान्यतः रोज़गार युक्त का कार्यहीनता का आपात, साप्ताहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत |

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

उपरोक्त विश्लेषण में हमने सामान्य स्थिति तथा चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोज़गारी के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त यह जानना भी महत्त्वपूर्ण होगा कि चालू साप्ताहिक अवधारणा के आधार पर रोज़गार-युक्त व्यक्तियों को कुल कितने दिन का रोज़गार प्राप्त हुआ। यदि एक व्यक्ति 183 या अधिक दिनों तक रोज़गार युक्त होता है तो उसे मुख्य श्रमिक (main worker) कहेंगे।

तालिका 20.4

**साप्ताहिक स्थिति के आधार पर रोज़गार युक्त व्यक्तियों का एक सप्ताह में कार्य दिवसों का वितरण**

**(प्रति हजार रोज़गार युक्त)**

| एक सप्ताह में | ग्रामीण | | शहरी | | सभी क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्य दिवस | पुरुष | महिलाएँ | पुरुष | महिलाएँ | पुरुष | महिलाएँ | व्यक्ति |
| 0.5–1.5 | 5 | 11 | 33 | 14 | 5 | 12 | 7 |
| 1.5–3.5 | 28 | 87 | 14 | 59 | 26 | 84 | 44 |
| 3.5–5.5 | 67 | 246 | 37 | 183 | 62 | 239 | 118 |
| 5.5–6.5 | 27 | 36 | 35 | 38 | 29 | 36 | 31 |
| 6.0–6.5 | 873 | 620 | 911 | 706 | 878 | 629 | 800 |
| | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

तालिका 20.4 से पता चलता है कि चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर रोज़गार युक्त पाए गए 5 प्रतिशत वास्तव में केवल तीन अथवा उससे कम दिन रोज़गार प्राप्त कर सके। ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में यह पता चलता है कि ग्रामीण महिलाएँ जो चालू साप्ताहिक अवधारणा के अनुसार हालाँकि रोज़गार युक्त मानी गई लेकिन उनमें से 10 प्रतिशत को

तीन अथवा कम दिनों के लिए रोज़गार प्राप्त हो सका।

## 20.5.5 शिक्षा एवं बेरोज़गारी

बेरोज़गारों की विशेषताओं का ज्ञान, बेरोज़गारी की समस्या का निदान के लिए आवश्यक है। बेरोज़गारों की विशेषताओं से यह पता चलता है कि श्रमशक्ति, जो काम की तलाश में है, उनके लिए किस प्रकार के रोज़गारों के अवसरों की आवश्यकता होगी। 1980 के बाद बेरोज़गारों की शिक्षा संबंधी विशेषताओं में भारी परिवर्तन हुआ है। जनगणना का विस्तृत विश्लेषण तथा बेरोज़गारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की नमूना विधि दोनों से यह पता चलता है कि बेरोज़गार लोगों में साक्षरों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।

**तालिका 20.5**

**भारत में बेरोज़गारों के शिक्षण का संदर्भ**

| वर्ष | निरक्षर | शिक्षा का स्तर | | | शिक्षित | सभी रोज़गार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राथमिक | माध्यमिक | उच्चतर तथा अपर | | |
| जनगणना (सभी आयु वर्गों के लिए)[1,2,3] | | | | | | |
| 1981 | 29.62 | 14.57 | 16.84 | 38.97 | 70.38 | 100.00 |
| 1991 | 19.56 | 12.17 | 20.89 | 47.38 | 80.44 | 100.00 |
| रोज़गार एवं बेरोज़गारी के सैम्पल सर्वे (आयु 15 वर्ष तथा अधिक) | | | | | | |
| 1983 | 6.10 | 19.32 | 27.58 | 47.00 | 93.90 | 100.00 |
| 1993-94 | 5.24 | 11.01 | 20.20 | 63.55 | 94.76 | 100.00 |

**नोट** :

1) जनगणना में बेरोज़गारी की पहचान के लिए अपनाई गई अवधारणा, राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के रोज़गार एवं बेरोज़गारी में प्रयुक्त अवधारणा के समान नहीं है।

2) 'काम नहीं कर रहे' वर्ग के लोगों के आर्थिक सहायक स्थिति का ध्यान रखते हुए, सैम्पल सर्वे अनुमान साधारण गतिविधि के आधार पर है।

3) 1991 की जनगणना में सूचना करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में 100 प्रतिशत आँकड़ों को तालिकाबद्ध करके एवं 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 10 प्रतिशत सैम्पल आँकड़ों को तालिकाबद्ध करके प्राप्त की गई है।

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

## 20.5.6 महिलाओं में बढ़ती बेरोज़गारी का आपात

जैसा कि अपेक्षित ही है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में (खास तौर पर शहरी क्षेत्रों) महिलाओं का बहुत कम प्रतिशत श्रमशक्ति में सम्मिलित होता है। 1973 में ग्रामीण क्षेत्रों में 38 प्रतिशत महिलाएँ तथा 65 प्रतिशत पुरुष श्रमशक्ति में सम्मिलित थे। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत क्रमशः 17 एवं 60 था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेरोज़गारी का आपात यानि, रोज़गार रहित सप्ताह (अथवा दिवस) का श्रमशक्ति के कूल सप्ताह (अथवा दिवस) प्रतिशत, महिलाओं में अधिक एवं पुरुषों में कम पाया गया। 1972-73 में ग्रामीण क्षेत्र

में, रोज़गार विहीन व्यक्ति दिवस का प्रतिशत महिलाओं में 11 तथा पुरुषों में 7 था। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों की तदनरूप गणना 14 तथा 8 थी। 1993-94 में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

## 20.5.7 बेरोज़गारी का क्षेत्रीय आयाम—नवीं पंचवर्षीय योजना

साधारणतः समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में बेरोज़गारी, समष्टि परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। लेकिन बेरोज़गारी के संदर्भ में क्षेत्रगत वास्तविकताओं को जानना महत्त्वपूर्ण एवं रोचक हो जाता है। नवीं पंचवर्षीय योजना में रोज़गार के संदर्भ में क्षेत्रगत अंतरों को बताया गया है। यह रोज़गार के आयोजन में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। यदि हम क्षेत्रगत परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं करेंगे तो यह खतरा हो सकता है कि समष्टिगत आर्थिक आयोजन में महत्त्वपूर्ण आयामों पर ध्यान न दिया जाए। इस उद्देश्य से नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख राज्यों को चार महत्त्वपूर्ण श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

**तालिका 20.6**

**बेरोज़गारी बढ़त का क्षेत्रगत प्रारूप**

| क्रम संख्या | विशेषताएँ | राज्य |
|---|---|---|
| 1) | बढ़ती बेरोज़गारी और श्रमशक्ति की तीव्र वृद्धि | बिहार, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश। |
| 2) | बढ़ती बेरोज़गारी किंतु श्रमशक्ति की धीमी वृद्धि | केरल और पंजाब। |
| 3) | घटती बेरोज़गारी किंतु श्रमशक्ति की तीव्र वृद्धि | असम और हरियाणा। |
| 4) | घटती बेरोज़गारी और श्रमशक्ति की धीमी वृद्धि | आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, ओड़िशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल। |

प्रथम श्रेणी में आते हैं, बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जहाँ श्रमशक्ति का संभावित वृद्धि दर अधिक है जबकि रोज़गार सृजन की दर श्रमशक्ति वृद्धि दर से कम है। इससे अभिप्राय यह है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में इस श्रेणी में आने वाले राज्यों में बेरोज़गारी बढ़ेगी।

दूसरी श्रेणी में आते हैं केरल और पंजाब जहाँ श्रमशक्ति की संभावित वृद्धि-दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इन राज्यों में रोज़गार का सृजन कम होने के कारण, बेरोज़गारी बढ़ेगी।

तीसरी श्रेणी में आते हैं असम और हरियाणा। इस श्रेणी में आने वाले राज्यों में श्रमशक्ति की वृद्धि दर अधिक होने की संभावना है लेकिन रोज़गार सृजन की संभावना अपेक्षाकृत और भी अधिक है। इस कारण से बेरोज़गारी कम होने की संभावना है।

चौथी श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल आते हैं। इन राज्यों में श्रमशक्ति की वृद्धि-दर कम होने की संभावना है किंतु रोज़गार में वृद्धि-दर, श्रमशक्ति की वृद्धि-दर की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है। इससे बेरोज़गारी में कमी होने की संभावना है।

तालिका 20.7

**श्रम शक्ति एवं रोज़गार प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत राज्यों में नवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोज़गारी में लक्षित परिवर्तन**

| श्रम शक्ति एवं रोज़गार विशेषताएँ | राज्य | रोज़गार वृद्धि-दर (1997-2002) (प्रतिशत प्रतिवर्ष) | श्रमशक्ति वृद्धि-दर (1997-2002) | बेरोज़गारी 1997 | 2002 | परिवर्तन (000 व्यक्ति) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. बढ़ती | बिहार | 2.30 | 2.58 | 2153 | 2980 | 827 |
| बेरोज़गारी एवं | राजस्थान | 2.84 | 2.88 | 1023 | 1228 | 205 |
| श्रमशक्ति की | उत्तर प्रदेश | 2.20 | 2.57 | 933 | 2337 | 1405 |
| तीव्र वृद्धि | **क्षेत्र** | | | | | **2437** |
| 2. बढ़ती | केरल | 1.43 | 2.30 | 1373 | 2151 | 778 |
| बेरोज़गारी लेकिन | पंजाब | 0.73 | 2.27 | 380 | 1162 | 781 |
| श्रमशक्ति की धीमी वृद्धि | **क्षेत्र** | | | | | **1559** |
| 3. घटती | असम | 3.69 | 2.73 | 522 | 182 | −340 |
| बेरोज़गारी लेकिन | हरियाणा | 3.67 | 2.99 | 96 | −151 | −248 |
| श्रमशक्ति की | आंध्र प्रदेश | 3.28 | 2.39 | 617 | −979 | −1596 |
| तीव्र वृद्धि | गुजरात | 2.55 | 2.37 | – | −233 | −233 |
| | कर्नाटक | 3.01 | 2.40 | – | −659 | −659 |
| | **क्षेत्र** | | | | | **-659** |
| 4. घटती | मध्य प्रदेश | 2.71 | 2.39 | 1722 | 1428 | −294 |
| बेरोज़गारी और | ओड़िशा | 2.54 | 2.10 | 633 | 386 | −24 |
| श्रमशक्ति धीमी | महाराष्ट्र | 2.70 | 2.26 | – | −996 | −996 |
| वृद्धि | तमिलनाडु | 2.2 | 1.98 | 28 | −370 | −398 |
| | प. बंगाल | 3.15 | 2.52 | 256 | −655 | −911 |
| | **क्षेत्र** | | | | | **-5333** |
| **संपूर्ण भारत** | **2.62** | **2.54** | **7500** | **6630** | **-870** | |

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

**बोध प्रश्न 4**

1) भारत में बेरोज़गारी के मापन के लिए प्रयुक्त तीन अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में शिक्षित बेरोज़गारी की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत में बेरोज़गारी की समस्याओं के क्षेत्रीय आयाम की चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.6 बेरोज़गारी के निवारण के लिए सरकारी नीति

भारत की आर्थिक आयोजन में बेरोज़गारी की समाप्ति हमेशा से ही मूल उद्देश्य माना गया है। लेकिन हम छठी पंचवर्षीय योजना तक बेरोज़गारी के उन्मूलन के लिए कोई दीर्घकालीन नीति नहीं बना पाए।

### 20.6.1 नवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व रोज़गार नीति

आर्थिक आयोजन के प्रारंभ में आर्थिक संवृद्धि को एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। ऐसा सोचा गया कि बेरोज़गारी उन्मूलन हेतु प्रत्यक्ष उपायों से संवृद्धि प्रक्रिया धीमी हो सकती है। 1970 के दशक के अंत में ही बेरोज़गारी की समस्या के निवारण हेतु प्रत्यक्ष उपाय अपनाने प्रारंभ किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में दो प्रमुख उद्देश्य तय किए गए। (i) श्रमशक्ति के अल्प रोज़गार में कमी, तथा (ii) दीर्घकाल में बेरोज़गारी में कमी।'

चौथी पंचवर्षीय योजना में भी यह अपेक्षा की गई थी कि बेरोज़गारी के लिए जागरूक नीति अपनाने की आवश्यकता है। इसमें ग्रामीण विकास, श्रम-प्रधान सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम, उद्योगों में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी तथा घरेलू तथा विदेशी बाज़ारों के लिए श्रम प्रधान औद्योगिक उत्पादों के वृद्धि पर बल दिया गया। लेकिन यह नीति मात्र कागज़ पर ही रह गई क्योंकि सरकार ने निवेश के प्रति अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भी बेरोज़गारी उन्मूलन को एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया। कहा गया कि वितरण में न्याय के लिए भी बेरोज़गारी उन्मूलन महत्त्वपूर्ण है। फिर से श्रम प्रधान परियोजनाओं के चयन पर जोर दिया गया और स्वरोज़गार द्वारा भी रोज़गार सृजन पर बल दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना में यह जिक्र किया गया कि पिछले वर्षों में रोज़गार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। यह स्वीकार किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार सृजन की अधिक संभावना नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र में श्रम की माँग तथा उसके उपयोग को प्रभावित करने की आवश्यकता है। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा गैर कृषि कार्यों में स्वरोज़गार सृजन पर भी बल दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सभी के लिए रोज़गार का लक्ष्य रखा गया। श्रम-नीति का खुलासा करते हुए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि रोज़गार वृद्धि-दर ऊँची करने के लिए उत्पादन में ऊँची वृद्धि-दर आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जब संवृद्धि में उन क्षेत्रों का अधिक योगदान हो जिनके उत्पादन में रोज़गार का हिस्सा तथा श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग अधिक हो तब संवृद्धि के रोज़गार सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि तथा उत्पादन संरचना के पुनर्गठन से ही रोज़गार संवृद्धि संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रम के अधिक तथा कुशल उपयोग से ही आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि संभव है लेकिन यह अन्य संसाधनों जैसे पूँजी, आंतरिक तथा अतिरिक्त माँग की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगा।

यह कहा गया है कि संवृद्धि के रोज़गार सृजन क्षमता को उत्पादन के पुनर्गठन द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। उन क्षेत्रों को बढ़ावा मिले जिसमें प्रति इकाई उत्पादन में अधिक रोज़गार प्राप्त होता हो।

यह कहा गया कि यदि 1997 तक पूर्ण रोज़गार के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोज़गार वृद्धि-दर को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाना होगा, और यदि इस लक्ष्य को सन् 2000 तक पूरा करना है तो रोज़गार वृद्धि-दर को 3 प्रतिशत तक रखना होगा। क्षेत्रगत रोज़गार सृजन के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, पशुपालन, मत्स्य–पालन, वन विकास तथा प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि और वन, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, आधुनिक लघु उद्योग के विकास पर बल दिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद भी रोज़गार नीति में दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य का अभाव रहा। हर पंचवर्षीय योजना में नई योजनाएँ आती रहीं और कई पुरानी योजनाओं को रद्द कर दिया गया और पुरानी गलतियों से कुछ शिक्षा नहीं ली गई।

### 20.6.2 नवीं पंचवर्षीय योजना में रोज़गार परिदृश्य

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोज़गार की संवेदनशील होने की अपेक्षा है। यानि उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा रोज़गार में 0.38 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा है। नवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत की संवृद्धि दर होने की अपेक्षा है, जिसका अर्थ यह है कि 540 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजन की अपेक्षा है। इसी काल में श्रमशक्ति में वृद्धि 530 लाख होगी, जिसका अभिप्राय यह है कि इस दौरान बेरोज़गारी 10 लाख कम हो जाएगी। लेकिन यदि हम इस अपेक्षित संवृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमारी बेरोज़गारी पहले से कहीं अधिक हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि संवृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रह जाए तो बेरोज़गारों की संख्या पहले के अपेक्षा 60 लाख अधिक हो जाएगी।

तालिका 20.8 अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में अपेक्षित वृद्धि दर्शाती है। इससे पता चलता है कि रोज़गार के अवसरों में सर्वाधिक वृद्धि कृषि क्षेत्र से प्राप्त होगी, यानि 280 लाख। यह तभी संभव है कि इस क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की संवृद्धि दर रहे। यह अपेक्षित संवृद्धि दर अधिक प्रतीत होती है। योजना आयोग ने भी इसे स्वीकार किया है कि कृषि में 4.5 की संवृद्धि दर प्राप्त करना एक मुश्किल कार्य होगा।

तालिका 20.8

कार्य अवसरों के अनुमान (1997-2002)

| क्षेत्र | सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि (प्रतिशत प्रतिवर्ष) | कार्य अवसर (10 लाख) 1997 | 2002 |
|---|---|---|---|
| 1. कृषि | 4.50 | 237.31 | 265.24 |
| 2. खनन एवं उत्खनन | 7.70 | 2.89 | 3.62 |
| 3. विनिर्माण | 9.70 | 43.60 | 49.15 |
| 4. विद्युत | 10.60 | 1.52 | 1.15 |
| 5. निर्माण | 5.70 | 14.35 | 16.98 |
| 6. व्यापार एवं परिवहन | 7.10 | 46.80 | 56.68 |
| 7. वित्तीयण, संपदा, बीमा एवं व्यापारिक सेवाएँ | 10.10 | 4.25 | 5.52 |
| 8. सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएँ | 5.30 | 39.01 | 44.46 |
| **सभी क्षेत्र** | **7.00** | **389.73** | **443.62** |

**स्रोत** : नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002), योजना आयोग, भारत सरकार।

**बोध प्रश्न 5**

1) छठी पंचवर्षीय योजना के बाद होने वाली रोज़गार नीति में परिवर्तन का विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.7 रोज़गार कार्यक्रमों का विवरण

पिछले भाग में हमने देखा कि छठी पंचवर्षीय योजना तक बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कोई दीर्घकालीन नीति नहीं थी। आयोजन के प्रारंभिक वर्षों में जहाँ कोई स्पष्ट रोज़गार नीति नहीं थी, वहीं आर्थिक संवृद्धि को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना गया। यह समझा गया कि आर्थिक संवृद्धि से बेरोज़गारी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन आर्थिक संवृद्धि के बावजूद जनसाधारण की गरीबी दूर नहीं की जा सकी। इसके बाद यह समझा गया कि गरीबी की स्थायी उन्मूलन उत्पादक रोज़गार अवसरों में वृद्धि पर ही निर्भर होगी। यह भी समझा गया कि ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण उत्पादकता की निम्नस्तर तथा बेरोज़गारी के कारण है। इसलिए गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन पर निर्भर होना चाहिए।

कई प्रकार के बेरोज़गारी उन्मूलन कार्यक्रम इस चिंतन पर शुरू किए गए, विशेष तौर पर छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। यह तय किया गया कि इन रोज़गार सृजन कार्यक्रमों में :

1) उत्पादकता में वृद्धि हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, और
2) ग्रामीण जनसंख्या का वह हिस्सा जिसे अतिरिक्त रोज़गार की आवश्यकता है, को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

इस प्रकार ग्रामीण रोज़गार के कई कार्यक्रम अपनाए गए। इस भाग में इन्हीं कार्यक्रमों का विवरण देने का प्रयास किया जाएगा।

### 20.7.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (NREP) की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया। इस योजना को केन्द्र सरकार के कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया। लेकिन इसके आर्थिक भार को केन्द्र तथा राज्य सरकारों में बराबर बाँटने का प्रावधान रखा गया। केन्द्रीय वित्त में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निम्नलिखित दो आधारों पर तय किया गया : (i) गरीबी का आपात; और (ii) कृषि श्रमिकों, सीमांत कृषकों तथा सीमांत श्रमिकों की संख्या।

इन दोनों तत्त्वों को बराबर महत्त्व दिया गया यानि 50 प्रतिशत। इस योजना के अंतर्गत जिले के स्तर रोज़गार योजना का निर्माण किया गया (खंड के आधार पर)। इस योजना में कार्य के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या तथा उसमें कार्य अवसरों की संभावित उपलब्धता का अनुमान लगाने का प्रावधान था। उसी के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में परियोजना तैयार की जाती थी। योजना आयोग के अनुसार लागू करने वाली एजेंसियों को कहा गया कि वे इस योजना में सामाजिक वनारोपण तथा चरागाह विकास, मृदा तथा जल संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी, सिंचाई कमांड क्षेत्रों में चैनलों, ग्रामीण तालाबों तथा टैंकों के निर्माण एवं संरक्षण, स्कूल तथा चिकित्सालय भवनों, ग्रामीण पर्यावरण, सफाई एवं स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता दें।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को उस क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मजदूरी दी गई। मजदूरी आंशिक तौर पर नकद तथा आंशिक तौर पर अन्न के रूप में दी जाती थी। यह योजना 9 वर्ष तक चली तथा इसमें छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः 177.41 तथा 147.75 करोड़ श्रम दिवसों का रोज़गार प्रदान किया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि रोज़गार सृजन के ये दावे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हैं।

### 20.7.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)

यह कार्यक्रम (IRDP) 1978 में प्रयोग के तौर पर प्रारंभ किया गया और इसे 1980-81 में देश भर में विस्तार किया गया। यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का अंग था। कार्यक्रम का प्रारूप इस प्रकार से बनाया गया ताकि (i) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान हो सके, और (ii) इन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियाँ अथवा आवश्यक क्षमता उपलब्ध करवाते हुए स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध किए जा सकें।

यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ और आज तक जारी है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया और बैंकों से अपेक्षा थी कि इस कार्यक्रम हेतु वे 3000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएँगे और इसके द्वारा 1.5 करोड़ परिवार

लाभान्वित होंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 182 करोड़ परिवारों तथा 1990-96 में 1047 परिवारों की सहायता की गई। हालाँकि रोज़गार सृजन का सही अनुमान नहीं लगाया गया।

### 20.7.3 भूमिहीन ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)

भूमिहीन ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण के द्वारा ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना था। प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 कार्य दिवसों के लिए रोज़गार की गारंटी देने का उद्देश्य इस कार्यक्रम में रखा गया। इस योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार ने वहन किया जबकि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों को सौंपी गई। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में 2601.8 लाख कार्य दिवसों का रोज़गार तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 4 वर्षों में 11543.9 लाख कार्य दिवसों का रोज़गार इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया गया। इस योजना में उल्लेखनीय कार्य के बावजूद इसके सीमित दायरे के कारण, ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर करने में इसका कम योगदान रहा।

अप्रैल 1989 से भूमिहीन ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोज़गार योजना के साथ शामिल कर दिया गया।

### 20.7.4 जवाहर रोज़गार योजना (JRY)

जवाहर रोज़गार योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1989 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उत्पादक कार्यों में अतिरिक्त रोज़गार उपलब्ध करवाना था जो या तो गरीबों के लिए स्थायी तथा लाभकारी रूप से अथवा ग्रामीण संरचनात्मक ढाँचे में योगदान करे। इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार 80 प्रतिशत तथा राज्य 20 प्रतिशत योगदान देती है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता उस राज्य में निर्धनों के कुल निर्धनों के अनुपात में दी जाती है।

जवाहर रोज़गार योजना में सभी ग्रामीण कार्य आते हैं जिनसे सामूहिक उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। निर्धनों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, लाभान्वित वर्गों के चयन में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है एवं महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण रहता है।

जवाहर रोज़गार योजना के प्रथम सात वर्षों में 620.1 करोड़ श्रम दिवसों के रोज़गार का सृजन किया गया। इस कार्यक्रम की मात्रात्मक उपलब्धियाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम से बेहतर है।

1) इस कार्यक्रम में आर्थिक रूप से उत्पादक निवेश को प्राथमिकता दी जाती है जिससे भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
2) रोज़गार कार्यक्रमों की योजना तथा क्रियान्वयन में पंचायतों का योगदान लिया जाता है।

### 20.7.5 ग्रामीण युवकों के लिए स्व-रोज़गार हेतु प्रशिक्षण (TRYSEM)

ग्रामीण युवकों को बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए तैयार करने हेतु यह योजना 1979 में प्रारंभ की गई। इसमें 3500 रुपये प्रतिवर्ष की आय से कम, गरीबी की रेखा से नीचे

रहने वाले युवकों में परंपरागत कुशलताओं कि सुधार करने का उद्देश्य रखी गई। चयन करते वक्त अनुसूचित जाति या जनजातियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी गई। 9.4 लाख युवकों को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षित किया गया और 4.64 लाख युवकों ने स्वरोज़गार प्राप्त किया। प्रशिक्षितों में 34.8 प्रतिशत महिलाएँ और 31.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबद्ध थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8.73 लाख गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को युवकों को प्रशिक्षित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में 1990-91 से 1995-96 के छः वर्षों में इस योजना ने 17.03 लाख ग्रामीण युवकों को लाभान्वित किया।

**बोध प्रश्न 3**

1) ऐच्छिक बेरोज़गारी से आपका क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

## 20.8 सारांश

इस इकाई में दिए गए विवेचन से स्पष्ट है कि बेरोज़गारी उन्मूलन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लेखनीय प्रयास किए गए। लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इन योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन में वास्तविक लाभ धनवान लोगों द्वारा उठा लिया गया। ऐसा इसलिए है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों पर अनावश्यक निर्भरता रखी गई जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारत जैसे अल्पविकसित देशों में बेरोज़गारी की समस्या व्याप्त है। यह बात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। धीमी संवृद्धि प्रक्रिया, श्रमशक्ति में तीव्र वृद्धि, अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा अनुपयुक्त श्रमशक्ति आयोजन इस समस्या के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं। बेरोज़गारी की समस्या के मापन के लिए कई प्रकार के मापक अपनाए जाते हैं। इस समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए; जैसे शिक्षा एवं बेरोज़गारी, महिलाओं में बेरोज़गारी तथा बेरोज़गारी का क्षेत्रीय वितरण।

## 20.9 शब्दावली

**ब्लू कॅलार बेरोज़गारी** : कुशल/अकुशल शारीरिक श्रमिकों में व्याप्त बेरोज़गारी।

**प्रच्छन्न बेरोज़गारी** : अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी की स्थिति में कम लोगों के लिए कार्य उपलब्ध होता है जबकि उसी कार्य को अधिक लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोगों को निकाल लिया जाए तो कुल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, यदि बचे हुए लोग अपनी पूरी क्षमता से कार्य

**रोज़गार की लोच** : यह आय/उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप रोज़गार में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता का मापक है। रोज़गार की लोच निम्न प्रकार से मापी जा सकती है :

$$= \frac{\text{रोज़गार में प्रतिशत परिर्वतन}}{\text{आय अथवा उत्पादन में प्रतिशत परिर्वतन}}$$

**श्रमशक्ति आयोजन** : समाज की आवश्यकताओं का आकलन और तदनुसार श्रम संसाधनों का विकास।

**मुख्यतः श्रमिक** : एक श्रमिक जो किसी एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों तक रोज़गार युक्त हो वह मुख्यतः श्रमिक कहलाएगा।

**व्यक्ति सप्ताह** : एक व्यक्ति कार्यरत (यानि रोज़गार युक्त) माना जाएगा, यदि उसने सर्वे से पूर्व के सप्ताह में किसी एक भी दिन में कार्य किया हो।

**व्हाइट कॅलार बेरोज़गारी** : शिक्षित वर्ग के बीच बेरोज़गारी।

## 20.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002, भाग-1, भारत सरकार, योजना आयोग, नई दिल्ली, अध्याय-IV।

*Indian Economy*, S.K. Misra and V.K. Rai 1997, Himalya Publishing House, Chapter-9.

M.L. Dantwala, *Understanding Poverty and Unemployment in Indian Economy Since Endependence* (ed.) Uma Kapila, 1993, Academic Foundation, Delhi.

*Indian Economy*, Ruddar Dutt and KPM Sundaram (1997) Chapter 24.

## 20.11 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) ऐच्छिक बेरोज़गारी वह परिस्थिति है जब लोग या तो किसी लाभकारी रोज़गार में इच्छुक नहीं होते अथवा श्रम बाजार में चालू मजदूरी से अधिक पर कार्य के लिए इच्छुक होते हैं।

2) अनैच्छिक बेरोज़गारी ऐसी परिस्थिति है जब लोग चालू मजदूरी दरों पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन इन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं होते।

3) विकसित देशों में चक्रीय बेरोज़गारी तथा घर्षण बेरोज़गारी पाई जाती है जो क्रमशः प्रभावी माँग के अभाव तथा नई प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण उत्पन्न होती है। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारण अल्पविकसित देशों में श्रम की माँग कम होती है। दोनों ही प्रकार के देशों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी अनैच्छिक बेरोज़गारी ही मानी जाएगी।

**बोध प्रश्न 2**

1) i) मौसमी बेरोज़गारी
   ii) प्रच्छन्न बेरोज़गारी

2) उपभाग 20.3.1 का संबंधित भाग देखें।

3) i) अप्रशिक्षित औद्योगिक (ब्लू कॅलार) श्रमिकों की बेरोज़गारी
   ii) शिक्षित वर्ग (व्हाइट कॅलार) की बेरोज़गारी
   iii) पार्ट टाइम के लिए काम के इच्छुक विद्यार्थी इत्यादि
   विस्तृत विश्लेषण के लिए उपभाग 20.3.2 देखें।

**बोध प्रश्न 3**

1) i) धीमी प्रगति प्रक्रिया
   ii) श्रमशक्ति में वृद्धि
   iii) अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी
   विस्तृत विश्लेषण के लिए भाग 20.4 देखें।

**बोध प्रश्न 4**

1) i) सामान्य स्थिति बेरोज़गारी
   ii) चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी
   iii) चालू दैनिक स्थिति बेरोगारी

   विस्तृत विश्लेषण के लिए भाग 20.5 देखें।

2) उपभाग 20.5.5 देखें।

3) उपभाग 20.5.7 देखें।

**बोध प्रश्न 5**

1) भाग 20.6 देखें।

**बोध प्रश्न 6**

1) भाग 20.7 देखें।